

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 716
उत्तर देने की तारीख- 24.07.2025

पीएम-जुगा की कार्यान्वयन स्थिति

716. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जुगा) के अंतर्गत चयनित गांवों की राज्यवार संख्या सहित ब्यौरा क्या है और उनके चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में पीएम-जुगा के अंतर्गत चिन्हित गांवों की जिलेवार संख्या सहित ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) संपूर्ण देश में उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और कार्यान्वित प्रस्तावों का घटकवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश में जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(घ) संपूर्ण देश में पीएम-जुगा की शुरुआत से लेकर अब तक उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई वर्षवार/राज्यवार कुल निधि कितनी है और आंध्र प्रदेश में जिलेवार कुल निधि कितनी है; और

(ङ) उक्त योजना से अब तक लाभान्वित अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों और व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है और आंध्र प्रदेश में जिलेवार संख्या कितनी है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) तथा (ख) : माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढाँचे की अंतरों को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। यह अभियान 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले विशिष्ट जनजातीय बहुल गांवों, जहां कम से कम 50% जनजातीय लोग हों, तथा आकांक्षी ब्लॉकों में कम से कम 50 जनजातीय लोगों की जनसंख्या वाले गांवों को लक्षित करता है। राज्यों को मिशन के अंतर्गत अनुमोदित अंत्योदय अंतरों के आँकड़ों के अनुसार चयनित 63,843 गांवों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। यदि राज्य को लगता है कि 63,843 की सूची में कोई गाँव छूट गया है, जो अन्यथा मानदंडों को पूरा करता है, तो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश उस गाँव को अभियान के अंतर्गत शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। देश भर में पीएमजेयूजीए/डीएजेजीयूए के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित गांवों की संख्या और विवरण जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं और संबंधित लिंक यहां संलग्न है (<https://tribal.gov.in/dajagua.aspx>)

(ग) और (ड.): संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) सहित विभिन्न लाइन मंत्रालयों/विभागों की अनुमोदित और कार्यान्वयन स्थिति का विवरण **अनुलग्नक I** में संलग्न है।

(घ): योजना के अंतर्गत कुल निधियों का आवंटन, स्वीकृत राशि और निर्मुक्ति नीचे दी गई है:

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत, लक्ष्यों और वित्तीय आवंटन के साथ विभिन्न उपायों (हस्तक्षेपों) का मंत्रालय-वार विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय	उपाय/ (योजना)	लक्ष्य	वित्तीय स्थिति (करोड़ रुपये में)
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)	पक्के मकान - (पीएमएवाई - ग्रामीण)	20 लाख घर	33800
		संपर्क सड़क - (पीएमजीएसवाई)	25000 किमी सड़क	25000
2	जल शक्ति मंत्रालय	जल आपूर्ति - जल जीवन मिशन (जेजेएम)	(i) प्रत्येक पात्र गाँव (ii) 5,000 बस्तियाँ \leq 20एचएच	50
3	विद्युत मंत्रालय	गृह विद्युतीकरण- (नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना - आरडीएसएस)	प्रत्येक अविद्युतीकृत एचएच और असंबद्ध सार्वजनिक संस्थान	1528
4	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	ऑफ-ग्रिड सौर कनेक्शन - नई सौर ऊर्जा योजना।	(i) प्रत्येक अविद्युतीकृत घर और सार्वजनिक संस्थान जो ग्रिड के अंतर्गत नहीं आते हैं।	400
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	संचल चिकित्सा इकाइयाँ - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1000 एमएमयू तक	1694
		आयुष्मान कार्ड - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) - एनएचए	अभियान के अंतर्गत शामिल प्रत्येक पात्र परिवार	50
6	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	एलपीजी कनेक्शन - (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना)	25 लाख परिवार	550
7	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना - पोषण 2.0	8000 (2000 नए आंगनवाड़ी केन्द्र) एवं 6000 सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र का उन्नयन)	300
8	शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण-समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	1000 छात्रावास	2750
9	आयुष मंत्रालय	पोषण वाटिकाएँ - राष्ट्रीय आयुष मिशन	700 पोषण वाटिकाएँ	50

10	दूरसंचार विभाग	4जी/5जी नेटवर्क - सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (डीओटी)	5000 गाँव	500
11	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	कौशल भारत मिशन (मौजूदा योजनाएं)/प्रस्ताव	जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र	81
			1000 वीडिवीके, जनजातीय समूह आदि	100
12	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सहयोग से जनजातियों के लिए डिजिटल पहलें	पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ मंत्रालय-विशिष्ट पोर्टलों का विकास और एकीकरण	250
13	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएँ	एफआरए पट्टा धारक (~2 लाख)	2500
14	मत्स्य विभाग	मछली पालन सहायता - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)	10,000 सामुदायिक और 1,00,000 व्यक्तिगत लाभार्थी	375
	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	पशुधन पालन - राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8500 व्यक्तिगत/समूह लाभार्थी	75
15	पंचायती राज मंत्रालय	एफआरए पर क्षमता निर्माण - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	सभी ग्राम सभाएं और उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर एफआरए को देखने वाले संबंधित अधिकारी	30
16	पर्यटन मंत्रालय	जनजातीय गृह प्रवास (होम स्टे) - स्वदेश दर्शन	1000 जनजातीय गृहों के लिए प्रति इकाई 5 लाख रुपये तक (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये तक (नवीनीकरण) और ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक का सहायता।	60
17	जनजातीय कार्य मंत्रालय	डीएजेजीयू	अन्य उपायों (हस्तक्षेपों) को शामिल करके जनजातीय विकास / पीएमएएजीवाई के लिए एससीए के दायरे को बढ़ाना*	9013
*100 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, आश्रम विद्यालयों, छात्रावासों, सरकारी/राज्य जनजातीय आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार, सिकल सेल रोग (एससीडी) के लिए सक्षमता केंद्र और परामर्श सहायता, एफआरए और सीएफआर प्रबंधन उपायों (हस्तक्षेपों) के लिए सहायता, एफआरए प्रकोष्ठों की स्थापना, और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जनजातीय जिलों के लिए प्रोत्साहन के साथ परियोजना प्रबंधन निधि।				

अभियान के अंतर्गत शामिल योजनाएं मंत्रिमंडल द्वारा संबंधित योजनाओं के अनुमोदन के अधीन हैं।

18.07.2025 तक डीए-जेजीयू योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में आवंटन, निर्मुक्त राशि का विवरण - लाख में

क्र. सं.	राज्य	निधियों के लिए हिस्से का अनुमानित आवंटन (5 वर्ष) प्रति राज्य न्यूनतम @ 35 करोड़ रुपये, बड़े संघ राज्यक्षेत्रों के लिए @ 25 करोड़ रुपये और छोटे संघ राज्यक्षेत्रों के लिए @ 15 करोड़ रुपये	निधियों का हिस्सा 2 वर्ष (2024-25 और 2025-26)	पीएसी द्वारा अनुमोदित	2025-26 के लिए निर्धारण	2024-25 के दौरान जारी निधियां	2025-26 के दौरान जारी निधियां
क	ख	ग	घ	ड.	च	ज	झ
1	आंध्र प्रदेश	18481	8230	16947	8230	0.00	2057.5
2	अरुणाचल प्रदेश	6732	2998	3000	2998	0.00	749.5
3	असम	35686	15891	31419	2372	13518.69	
4	बिहार	10848	4831	682	2039.2	0.00	509.8
5	छत्तीसगढ़	73340	32659	7401.95	3732	3654.74	
6	गोवा	3500	1559	32.54	500		
7	गुजरात	68445	30479	17585	30479		7619.75
8	हिमाचल प्रदेश	3500	1559	2867	190	1368.734	
9	झारखंड	79897	35579	26332	35579		8894.75
10	कर्नाटक	28359	12629	968	5755		
11	केरल	3500	1559	2234	1559		389.75
12	मध्य प्रदेश	135,830.00	60487	51142	13597	9136.882	
13	महाराष्ट्र	80440	35821	58008	35821		8955.25
14	मणिपुर	7304	3253	1875	3253		813.25
15	मेघालय	20581	9165	0	3000		
16	मिजोरम	7441	3314	0	1000		
17	नागालैंड	12180	5424	5228	967.6	678.4	
18	ओडिशा	87498	38964	39687	5000	17422.8	
19	राजस्थान	78125	34790	24627	16748		4187.00
20	सिक्किम	3500	1559	3635	1559		389.75
21	तमिलनाडु	5499	2449	4135	461	1987.754	
22	तेलंगाना	22305	9933	643	9933		
23	त्रिपुरा	8203	3653	8169	3653		913.25
24	उत्तर प्रदेश	8587	3824	887	1000		

25	उत्तराखंड	3500	1559	292	1569		
26	पश्चिम बंगाल	43714	19466	15	1000		
27	जम्मू एवं कश्मीर	8805	3921	877	3921		
28	लद्दाख	2500	1113	0	440		
29	लक्षद्वीप	1500	668	0	200		
30	दमन और दीव	1500	668	0	200		
	कुल	8,71,300	388,000.00	308696	196756	47768	23163

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), जलशक्ति मंत्रालय (एमओजे) एवं विद्युत मंत्रालय (एमओपी)
मंत्रालय की मंत्रालय-वार राज्य-वार प्रगति

राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)		एमओजेएस		विद्युत मंत्रालय			
	स्वीकृत मकान	पूर्ण हो चुके मकान	स्वीकृत गाँव	संतुष्ट गाँव	स्वीकृत एचएच	विद्युतीकृत एचएच	स्वीकृत पीपी	विद्युतीकृत पीपी
आंध्र प्रदेश	1	1173	867	198	4921	1447	182	23
अरुणाचल प्रदेश	0	780	321	321	1938	0	9	0
असम	54553	59385	3005	1374	0	0	0	0
बिहार	16	208	698	678	7117	0	0	0
छत्तीसगढ़	290068	104181	6677	1347	39,579	1,667	0	0
गोवा	0	0	25	25	0	0	0	0
गुजरात	73399	34398	4247	4247	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	2345	262	264	264	93	0	7	0
जम्मू और कश्मीर	21	16368	387	111	13824	0	0	0
झारखंड	54651	1798	7039	1773	19467	0	1910	0
कर्नाटक	10363	1411	1080	612	4229	114	0	0
केरल	597	117	89	0	1080	122	17	0
लद्दाख	0	0	143	92	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	2	1	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	281439	41934	11228	4157	55795	42	650	7
महाराष्ट्र	334710	23743	4929	2662	6961	4397	0	0
मणिपुर	0	2577	508	117	0	0	0	0
मेघालय	0	37197	1428	944	0	0	0	0
मिजोरम	0	6474	379	379	0	0	0	0
नागालैंड	0	16379	605	489	0	0	0	0
ओडिशा	17785	68234	7494	3461	0	0	0	0
राजस्थान	129114	13657	5709	1012	82842	0	195	0
सिक्किम	0	8	119	90	0	0	0	0
तमिलनाडु	112	358	114	81	0	0	0	0
तेलंगाना	0	0	909	909	26525	774	672	0
त्रिपुरा	0	9252	353	36	7677	0	512	0
दादरा और नगर हवेली	0	765	76	76		0		0
दमन और दीव	0	8			0	0	0	0

उत्तर प्रदेश	0	64	516	354	6867	45	30	5
उत्तराखंड	0	23	128	106	207	46	19	4
पश्चिम बंगाल	0	270	3179	589	0	0	0	0
कुल योग	12,49,174	4,41,024	62,518	26,513	2,79,122	8,654	4,203	39

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) और संचार मंत्रालय (एमओसी) की मंत्रालय-वार प्रगति

राज्य का नाम	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		शिक्षा मंत्रालय	दूरसंचार विभाग	
	तैनात एमएमयू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	संचालित आंगनवाड़ी केंद्र	स्वीकृत छात्रावास	मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए स्वीकृत गांव	मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए कवर किए गए गांव
आंध्र प्रदेश	0	177	0	4	194	162
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	45	56	26
असम	6	49	0	209	140	105
बिहार	0	45	0	19	30	23
छत्तीसगढ़	3	0	0	42	305	154
गोवा	0	0	0	0	8	3
गुजरात	0	0	0	9	97	71
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2	20	162
जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	10	0
झारखंड	20	50	0	5	157	109
कर्नाटक	0	164	164	14	13	8
केरल	0	0	0	2	0	0
लद्दाख	0	0	0	1	17	8
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	6	66	0	104	527	315
महाराष्ट्र	0	0	0	22	574	351
मणिपुर	0	0	0	44	45	4
मेघालय	0	26	0	0	16	6
मिजोरम	0	41	0	13	22	11
नागालैंड	0	0	0	23	101	29
ओडिशा	26	0	0	40	571	328

राजस्थान	0	135	115	58	254	165
सिक्किम	0	0	0	5	0	0
तमिलनाडु	0	3	3	0	78	74
तेलंगाना	7	0	0	10	45	24
त्रिपुरा	0	119	0	15	68	51
दादरा और नगर हवेली						
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	3	34	17
उत्तराखंड	0	0	0	3	5	5
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	2	1
कुल योग	70	875	282	692	3,389	2,212

जनजातीय कार्य मंत्रालय की राज्य-वार प्रगति

राज्य का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय				
	टीएमएमसी	आश्रम स्कूल परियोजनाएँ	सीएफआर	एफआरए प्रकोष्ठ	सीओसी
आंध्र प्रदेश	6	175	0	1	1
अरुणाचल प्रदेश	2	128	0	0	0
असम	5	640	0	1	1
बिहार	3	5	0	1	0
छत्तीसगढ़	5	1160	400	1	1
गोवा	0	0	0	1	0
गुजरात	1	217	0	1	1
हिमाचल प्रदेश	3	45	10	1	0
जम्मू और कश्मीर	5	0	0	1	0
झारखंड	9	641	100	1	1
कर्नाटक	2	0	0	1	1
केरल	2	30	0	1	1
लद्दाख	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	4	526	300	1	2
महाराष्ट्र	6	160	0	0	1
मणिपुर	2	64	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0

नागालैंड	2	198	0	0	0
ओडिशा	5	527	100	0	1
राजस्थान	6	558	0	1	1
सिक्किम	2	49	0	0	0
तमिलनाडु	5	80	10	1	1
तेलंगाना	0	623	0	1	1
त्रिपुरा	2	36	0	1	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1	14	0	1	0
उत्तराखंड	0	0	0	1	1
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
कुल योग	78	5876	920	18	15